



## सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को मान्यता प्रदान की

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004](#) की संवैधानिक वैधता को आंशिक रूप से मान्यता प्रदान की तथा पुष्टि की कि उक्त कृष्टता के मानकों को बनाए रखने के लिये राज्य को [मदरसा शिक्षा को वनियमिति करने का अधिकार है](#)।

### मुख्य बिंदु

- **सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:**
  - न्यायालय ने घोषणा की कि **उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान, विशेष रूप से फाजलि (स्नातक) और कामलि (स्नातकोत्तर) स्तर पर, असंवैधानिक** थे।
  - ये प्रावधान [वशिवदियालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956](#) के साथ टकराव में थे, जो [संवधान की सातवीं अनुसूची](#) में [संघ सूची](#) की प्रवर्षिट 66 के अनुसार केंद्र के विशेष क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।
  - नरिणय में स्पष्ट किया गया कि यह **अधिनियम राज्य के कर्तव्य के अनुरूप है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले छात्र न्यूनतम स्तर की योग्यता प्राप्त कर सकें**। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वे समाज में प्रभावी रूप से भाग ले सकें और जीविकोपार्जन कर सकें।
  - न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि अल्पसंख्यकों को संवधान के [अनुच्छेद 30](#) के तहत अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है, परंतु यह अधिकार पूर्ण नहीं है।
    - अल्पसंख्यक संस्थानों में शैक्षिक मानकों को बनाए रखने में राज्य का वैध हति है और वह सहायता और मान्यता के लिये नयामक शर्तें लगा सकता है।
  - न्यायालय ने [समवर्ती सूची](#) की प्रवर्षिट 25 में 'शिक्षा' की व्यापक व्याख्या की तथा कहा कि यदि मदरसे धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं, उनका **प्राथमिक उद्देश्य शैक्षिक है, इसलिये वे इस प्रवर्षिट के दायरे में आते हैं**।
    - मदरसा बोर्ड परीक्षा आयोजित करता है और छात्रों को प्रमाण पत्र जारी करता है, जो शैक्षिक ढाँचे के साथ संरेखित होता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नरिणय को खारजि कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 2004 का अधिनियम [अनुच्छेद 21A \(शिक्षा का अधिकार\)](#) और संवधान के [धर्मनरिपेक्षता](#) सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
    - न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21A की व्याख्या **धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकारों के साथ की जानी चाहिये**।
  - संवधान के [अनुच्छेद 28\(3\)](#) का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को **धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिये**, जिससे उनके [धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार](#) को सुनिश्चित किया जा सके।

### उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004

- इस अधिनियम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में **मदरसों (इस्लामी शैक्षणिक संस्थानों)** के कामकाज को वनियमिति और संचालित करना था।
- इसने उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थापना, मान्यता, पाठ्यक्रम और प्रशासन के लिये एक रूपरेखा प्रदान की।
- इस अधिनियम के तहत राज्य में मदरसों की गतिविधियों की देख-रेख और पर्यवेक्षण के लिये **उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई**।

